

कुल 213.38 कोड रुपये की [अनु-मोदित की गई थी, जिसकी वित्त-व्यवस्था के लिए 160.06 करोड रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा अपने संनाधनों से जुटाई जानी थी और 53.32 करोड रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में आवंटित किए गए थे। अनुमोदित परिषद के क्षेत्रवार वितरण का बिवरण मन्त्रालय पर प्रस्तुत है। [मन्त्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10456/76]

(ग) राज्य के पिछड़े क्षेत्रों से जन-जातीय क्षेत्रों की संख्या अधिक है। इन क्षेत्रों के लिए एक उप-योजना बनाई गई है जिसके लिए धन की व्यवस्था सामान्य राज्य योजना के आवंटनों और इसके लिए दी गई अनिश्चित केन्द्रीय सहायता से की गई है। जनजातीय क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेष केन्द्रीय निधि से इस वर्ष राज्य को 506 लाख रुपये अनिश्चित राशि के रूप में आवंटित किए गए थे।

आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

715. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के किन-किन स्थानों में सरकार आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना करना चाहती है,

(ख) क्या इन राज्यों में लगाये जा रहे ट्रांसमीटर उतने शक्तिशाली नहीं हैं जिनसे सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ पहुंच सके, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों में अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने का है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्रि (श्री बर्सेवीर सिंह) : (क) आकाशवाणी के केन्द्र फिलहाल निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किये जा रहे हैं :—

1 मध्य प्रदेश

- (1) अम्बिकापुर
- (2) छतरपुर
- (3) जगदलपुर
- (4) रीवां

2 राजस्थान

- (1) सूरतगढ

(ख) और (ग) इन स्थानों पर लगाए जा रहे ट्रांसमिटरों का उद्देश्य राज्य के भीतर यथा सभव अधिक से अधिक क्षेत्रों के लिए प्रसारण सेवा प्रदान करना है। उपर्युक्त परियोजनाओं के मुकम्मल हो जाने पर, मध्य प्रदेश के लगभग 85 प्रतिशत क्षेत्र और 87 प्रतिशत जनसंख्या तथा राजस्थान के 77 प्रतिशत क्षेत्र और 78 प्रतिशत जनसंख्या के लिए प्राथमिक प्रसारण सेवा उपलब्ध की जा सकेगी।

मोपेडों का उत्पादन

716. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग (आटोसाइकिल) बनाने वाली कितनी फैक्ट्रियां हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है,

(ख) कितनी फैक्ट्रियां निर्माणाधीन हैं और क्या इनमें उत्पादन इस वर्ष प्रारम्भ होने की संभावना है, और

(ग) मोपेड के विक्रय हेतु सरकार द्वारा अपनाई गई नीति क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जाजं) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र में मोपेडो का निर्माण करने वाला कोई एकक नहीं है। गैर सरकारी क्षेत्र में मोपेडो का निर्माण करने वाले पांच एकक हैं और 1975 में उनका उत्पादन 34,710 नग था। गैर सरकारी क्षेत्र को एक नये एकक में 5-2-76 से उत्पादन आरम्भ हो गया है। आशा है कि 1976 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र में एक एकक और गैर-सरकारी क्षेत्र में एक अनिश्चित एकक में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा।

(ग) सरकार ने 30-7-1975 से मोपेडो और आटो-माइकिलों की बिक्री और वितरण पर से कानूनी नियंत्रण हटा लिया है।

नेपा मित्स में अनियमितताये तथा घन का बुर्जिनियोग

717. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जुलाई, 1975 में कुछ समद सदस्यों से नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मित्स (नेपा मित्स), नेपालगंज में चल रही कतिपय अनियमितताओं तथा गोटालो के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और

(ग) उम पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० सी० शर्मा) : (क) से (ग) जुलाई, 1975 में समद सदस्यों से इस मंत्रालय में अनियमितताओं/

गवनों के बारे में कोई भी शिकायतें नहीं मिली हैं। फिर भी, एक समद सदस्य से मार्च, 1975 में मिली कुछ शिकायतों की जांच की जा रही है।

Scarcity of cement

718 PROF. NARAIN CHAND PARASHAR. Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether cement is available in the open market in some States,

(b) if so, names thereof;

(c) whether there is still scarcity of cement in some other states and cement is not available for domestic construction purposes even by the weaker sections of society; and

(d) if so, names of such States and steps being taken to remove the scarcity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SIRI B. P MAURYA) (a) to (d) Yes, Sir Cement is now available in open market almost in all the States. However, reports have been received from the Punjab that some scarcity of cement is being felt in a few towns of that State to improve the position, an additional allocation of about 40,000 tonnes has been made to the Punjab and supplies to these areas are being stepped up on urgent basis.

Programmes by A.I.R. to highlight the 13 Point Plan for Prohibition

719. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether any special effort has been made by the All India Radio to highlight the importance of the 13-point plan for promoting prohibition